

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1936 (शO) पटना, मंगलवार, 30 सितम्बर 2014

(सं0 पटना 796)

सं0 02/सी०-3044/2008,सा०प्र०-8272 सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प 18 जून 2014

श्री रिव भूषण, (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक—857 (08, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराचट्टी, गया के विरूद्ध बाराचट्टी प्रखंड कार्यालय की चहारदीवारी पर कंटीले तार लगाये जाने में बरती गई वित्तीय अनियमितता, योजना स्थल पर किया गया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप नहीं होने, गलत विपत्र का सत्यापन करने, प्रशासनिक विफलता, योजना के कार्यन्वयन में नियंत्रण का अभाव तथा अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं होने, पर्यवेक्षण सही ढंग से नहीं करने एवं कार्य का गलत प्रमाण—पत्र देने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री भूषण (बि॰प्र॰से॰) द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, जिला पदाधिकारी, गया द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) में निहित प्रावधानों के आलोक में इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संकल्प सं॰—6223 दिनांक 20.06. 2008 द्वारा संचालित किया गया। संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को नियुक्त किया गया।

- 2. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया—सह—संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही में सुनवाई के पश्चात् अपने पत्रांक—4364 दिनांक 12.12.2008 के द्वारा अपना जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित विभाग को समर्पित किया गया।
- 3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, प्रतिवेदित आरोप पर आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार के निर्णयानुसार श्री भूषण को संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया गया एवं बिहार लोक सेवा आयोग से सहमित प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया।
- 4. श्री भूषण के विरूद्ध सरकार द्वारा लिये गये निर्णय, प्रतिवेदत आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा कारण—पृच्छा की प्रति, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को विभागीय पत्रांक—10944 दिनांक 09.11.2009 के द्वारा प्रेषित करते हुए श्री भूषण के विरूद्ध प्रस्तावित दंड पर सहमति की माँग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ने पत्रांक—396 दिनांक 28.05.2010 द्वारा संसूचित दंड पर अपनी सहमति प्रदान की।
- 5 श्री रवि भूषण (बि॰प्र॰से॰) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (vi) विभागीय संशोधित अधिसूचना सं॰—2797 दिनांक 20.08.2007 के तहत विभागीय संकल्प सं॰—73 दिनांक 04.01.2011 द्वारा संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोके जाने संबंधी दंड संसूचित किया गया।

6. उक्त दंड के विरूद्ध श्री रवि भूषण के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी०सं०—16246 / 2011 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2012 को आदेश पारित किया गया जिसका कार्यकारी अंश निम्न प्रकार है :--

"In the facts and circumstances of the case, accordingly the order of punishment is modified to the extent of the stoppage of two increments with non-cumulative effect. With the above, the petition is disposed of."

7. उक्त न्यायादेश के विरूद्ध श्री रवि भूषण द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय में एल०पी० सं०–545/2013 दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2013 को आदेश पारित किया गया।

एल०पी०ए० सं०-545 / 2013 में पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्न प्रकार है :--

"In that view of the matter, the order dated 20.09.12 and the order for punishment dated 04.01.2011 are both set aside.

A revision filed by the appellant has been rejected on 29.06.2011. A bare perusal of the order of the Revisional Authority discloses complete non-application of mind as it does not, even consider the grounds taken in the revision, much less rejecting them by a reasoned and speaking order.

The appeal is allowed. "

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में इस विभाग द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प सं०–73 दिनांक 04.01.2011 जिसके द्वारा संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धियाँ रोके जाने का दंड संसूचित किया गया था, वापस लेते हुए निरस्त इस शर्त के साथ किया जाता है, कि एल०पी०ए०सं०–545 / 2013 में पारित आदेश के विरूद्ध सरकार ने एस०एल०पी० दायर करने का निर्णय लिया है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० में पारित आदेश से यह आदेश आच्छादित रहेगा। यदि एस०एल०पी० में आदेश सरकार के पक्ष में होता है, तो उस आदेश के तहत श्री रिव भूषण को दी गई सभी तरह के आर्थिक एवं प्रोन्नित लाभ उनसे वापस लिया जा सकेगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेजा दी जाये।

> बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अनिल कुमार, सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 796-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in